12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार–विमर्श कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 29–30 जून–जयपुर। **राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी. एस. व्यास** ने **12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार–विमर्श कार्यशाला में** अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य का आयोजना बोर्ड एक सलाहकारी बोर्ड है जो योजना निमार्ण प्रक्रिया में परामर्शदाता के रुप में भूमिका अदा करता है। प्रो. व्यास ने राज्य द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के कारण पंचायती राज संस्थाओं पर ध्यान कम दिए जाने को चिंताजनक बताया और कहा कि पंचायतों की केवल ऐजेंसी भूमिका नहीं है बल्कि पंचायतें शासन की ईकाई हैं। श्री व्यास ने कहा कि आगामी समय में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु उन्हे भौतिक व वित्तीय संसाधनों के साथ मानवीय संसाधनों की उपलब्धता करवाई जाएगी। कार्यशाला के दूसरे दिन चर्चा के दौरान प्रो. व्यास ने राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों से अवगत कराया और बताया कि इन परिणामों के आधार पर राज्य की 12वीं पंचवषीय योजना के लक्ष्यों एवं उद्वेश्यों का निर्धारण किए जाने में मदद मिलेगी। **कार्यशाला में मांग की गई कि जिला आयोजना समितियों द्वारा बनाए जा रहे जिला विकास आयोजना को राज्य आयोजना में समाहित करने के उपाय किए जाने चाहिए।**

12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार–विमर्श कार्यशाला का आयोजन बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र जयपुर द्वारा राज्य संदर्भ केन्द्र स्थित सभागार में किया गया। कार्यशाला का प्रमुख उद्वेश्य राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सिविल सोसायटी एवं राज्य के विभिन्न संगठनों की चिंताओं तथा सुझावों को सरकार तथा राज्य आयोजना समिति तक पहुंचाना था।

कार्यशाला के प्रथम दिवस की शुरुआत में विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. सुरजीत सिंह ने राज्य में आयोजना के वर्तमान परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा की। प्रो सिंह ने बताया कि राज्य में बजट और आयोजना निर्माण की पहले से चली आ रही प्रक्रिया के कोई बदलाव नहीं आया है जिसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार बजट निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों से चर्चा की जाती है उसी प्रकार योजना निर्माण में भी की जानी चाहिए। कार्यशाला में सुझाव दिया गया कि राज्य आयोजना बनाने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए, जिला स्तर पर बनाए जाने वाले योजना प्रारुप को राज्य के योजना प्रारुप में शामिल किया जाना चाहिए एवं राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरुप राज्य की कृषि नीति बनाई जानी चाहिए।

कार्यशाला के अगले सत्र में जल एवं सिंचाई मामलों के विशेषज्ञ प्रो. एम. एस. राठौड़ ने राज्य में जल समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य में अनियंत्रित जल विदोहन के कारण लगातार गिरते भू–जल स्तर पर नियंत्रण किया जाना चाहिए साथ ही जल

संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने के क्षेत्र में राज्य में जल नीति, जल अंकेक्षण व्यवस्था लागू किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही प्रो. राठौड़ ने शहरों तथा गांवों के जल की आवश्यकताओं के लिए अलग अलग आयोजना एवं कार्यक्रम की आवश्यकता बताया। प्रथम दिवस के अन्तिम सत्र में श्री बालमुकुन्द, सेवानिवृत्त मुख्य अभिन्यता, विद्युत बोर्ड एवं श्री भागवत नन्द, ने राज्य में उर्जा क्षेत्र में ध्यान दिए जाने की आवश्यता जताई जिसमें विशेषतौर पर राज्य में वैकल्पिक उर्जा के क्षेत्र में व्याप्त अपार संभावनाओं के मद्वेनजर इस क्षेत्र को 12वीं योजना में विशेष प्रोत्साहन दिया जाना बताया।

कार्यशाला में राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में **शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास को अधिक प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया गया।** सामाजिक कार्यकर्ता श्री ओपी कुल्हरी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने पर जोर दिया। चर्चा के दौरान विकास अध्ययन संस्थान की डॉ. शोभिता राजगोपाल ने राज्य में महिला हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण एवं महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास किए जाने पर जोर दिया। इस सत्र की अध्यक्षता पीयूसीएल की कविता श्रीवास्तव ने की। कार्यशाला के अगले सत्र में राज्य में अनुसूचित जाति एवं जन जाति उपयोजना के बारे में चर्चा की गई जिसके अंर्तगत इन योजनाओं में मानदंड के अनुरुप सरकार द्वारा अधिक राशि आंवटन किए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही सभी विभागों द्वारा इन दो उपयोजनाओं के तहत विशेष कार्यक्रम बनाने की मांग की गई जो सीधे दलितों तथा आदिवासियों को लाभान्वित करें। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुडी अल्का सिंह ने राज्य में आयोजना के विकेन्द्रीकरण किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दो दिवसीय कार्यशाला के अन्तिम सत्र का समापन प्रो. वी. एस. व्यास तथा आयोजना विभाग के श्री अनिल चपलोत के द्वारा की गई। कार्यशाला में राज्य की विभिन्न संस्थाओं एवं जनसंगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सत्र के अन्त में बजट अध्ययन

राजस्थान केन्द्र के समन्वयक नेसार अहमद ने दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान हुई चर्चा पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की ओर आगन्तुकों का आभार व्यक्त किया।

नेसार अहमद

समन्वयक

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर